(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SMT. KRISHNA SAHI): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Growth of paper industry

428. SHRI P. UPENDRA: Will the PRIME MINISTER to pleased to state:

(a) whether it is a fact that the growth of paper industry in the country is highly disappointing;

(b) whether it is also a fact that the industry has suggested a suitable policy package in consonance with the new industrial policy; and

(c) if so, what is the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SMT. KRISHNA SAHI): (a) There has been a steady growth in the Paper and Paper Board Industry. The Paper and Paper Board Industry is meeting the entire domestic demand and the imports are few, mainly restricted to some speciality papers such as art paper, cheque paper, photo-base paper, high strength craft paper, filter paper, cable and condenser paper, etc.

(b) and (c) There is constant interaction between the Government and the Industry and suitable policy measures are taken by Government whenever necessary.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाना

429. **श्री गोपाल सिंह जी॰ सोलंकी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने के लिये किसी उपक्रम के संबंध में कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में बनायी गई कार्यनीति का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य निष्पादन में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधकों और संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा उद्यम विशेष की आवश्यकता अनुसार कार्रवाई की जाती है। उठाए गए सामान्य कदम इस प्रकार हैं:

(I) सरकारी क्षेत्र और अधिक उपक्रमों को समझौता ज्ञापन के विचार क्षेत्र में लाया गया है जिसका उद्देश्य कार्य-निष्पादन में सुधार करना है।

(II) 38 रुग्ण उपक्रमों को उनके पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन संबंधी योजना बनाने हेतु औद्योगिक वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंप दिया गया।

(III) कार्य-निषपादन में सुधार हेतु उठाए गए अन्य कदमों का विवरण 5.3.1992 को सभा पटल पर रखे गए लोक उद्यम सर्वेक्षण 1990-91 के खण्ड-I के अध्याय 9 के पैरा 15.1 (पृष्ठ सं॰ 165) में दिया गया है।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, हटिया की वित्तीय स्थिति

430. **श्री गया सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, हटिया की वित्तीय स्थिति क्या है और अप्रैल, 1992 से जनवरी, 1993 तक की अवधि में इस कंपनी को कितना लाभ या हानि हुई है;

(ख) सरकार इस उद्योग का विकास करने और इसे

सुदृढ़ बनाने के लिये क्या कदम उठा रही है; और

(ग) इस उद्योग के बन्द हो जाने की स्थिति में सरकार को कितनी हानि होने की संभावना है और इसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कितने कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती कृष्णा साही): (क) एच०ई०सी० पिछले काफी समय से कठिन वित्तीय स्थिति का सामना कर रही है। अप्रैल, 1992 से जनवरी, 1993 तक की अवधि के दौरान, कंपनी को 102.02 करोड़ रुपये की निवल हानि हुई है।

(ख) वर्तमान वित्तीय संकट को दूर करने के लिए सरकार योजना और गैर-योजना निधियां प्रदान कर रही है, बैंकों के साथ नगद जमा सीमा में वृद्धि और बेशी जनशक्ति के युक्तिकरण के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन इत्यादि का कार्य भी कर रही है।

(ग) इसके बंद होने की स्थिति में, इसके उत्पादन के बड़े भाग का आयात करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, लगभग 15,300 व्यक्तियों का प्रत्यक्ष रूप से और अन्य 20,000 व्यक्तियों का परोक्ष रूप से रोजगार समाप्त हो जाएगा।

Deterioration in the functioning of the PSUs

431. PROF. SAURIN BHATTACHARYA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the functioning of some of the major public sector undertakings under his Ministry have been adversely affected and deteriorated in the past three months due to cuts in budgetary support, non-availability of working capital and Government's own orders;

(b) whether some units of these undertakings have reached conditions for total or partial closures;

(c) whether management of some of these undertakings have been forced to tender resignations; and

(d) if so, the details in this regard and the action Government have taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SMT. KRISHNA SAHI): (a) In the last three months the functioning of a few PSUs has been adversely affected by various factors like civil disturbances, recessionary trends in the market, infrastructural problems, poor order book position and shortage of funds including working capital etc.

(b) 19 PSUs of the Department are sick and have already been referred to BIFR.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Representations for financial support to PSUs

432. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in the past three months Government have received again large number of representations from various trade unions, organisations and Members of Parliament for providing actual financial support for sometime to enable the public sector undertakings to tide over their difficulties, mostly which are functioning under his administrative jurisdiction/Ministry of Industry;

(b) whether delay in taking a decision for funds has only aggravated the situations in Public Sector Undertakings and some of the managements have been forced to tender their resignation; and

(c) if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE